whether the Government has launched any massive programme to solve these problems and taken the initiative of people's participation in the programme and, also, what amount of funds allocated has been spent to benefit the poor.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Sir, I am thankful to the honourable Member for raising this question. I think this is the first question that has been raised so far as sanitation is concerned, and it has been done by an honourable lady Member. Here, while submitting the facts, because sanitation is the basic need of life, particularly in order to improve the quality of life in rural areas, of the rural people, particularly women and young girls, so far as sanitation facilities to be given to them are concerned, I would like to say that we have to give a lot of importance to them. But, unfortunately, it has not been taken up seriously by the State Governments. The State Government have not been doing very well in this area. We are going to take a serious view of it and we are going to write to the Chief Ministers to gear up the Administration. And we are going to come up with revised guidelines also. If required, I will be happy to receive suggestions from the honourable Members including the honourable lady Member who has put this question.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Sir, thank you for protecting my right of question: I thought it was taken away by the Opposition.

Sir, the honourable Minister has said in his answer given to the honourable lady Member from Orissa that she has shown concern about sanitation in the rural areas. I would like to ask the honourable Minister whether there is any coordinated programme with the Prime Minister's potable drinking water programme. Are you going to combine them together so that sanitation and potable water could be put together because both are connected with each other? The dirty water goes into the wells or the source of drinking water like a *talab*, etc. So, are you going to connect both together?

SHRI JANARDHAN POOJARI: Sir, the honourable Prime Minister is taking a lot of interest in this area and, in fact, that is why I have stated that we are coming up with new guidelines. All these suggestions, including this suggestion of the honourable Member, will be taken note of.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Thank you.

*84. [*The questioner (Shri M. Kadharsha) was absent. For answer* vide *col.* 35 infra].

*85. [*The questioner (Shri Chaturanan Mishra)* was *absent. For answer*, vide *col.* 35-36 infra]

चारे की नई किस्में

*86. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चारा तथा चरागाह अनुसंधान एवं विकास संस्थान, झांसी द्वारा विकसित की गई चारे की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन किस्मों को देश के प्रत्येक गांव में किसानों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू योजना की अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री)

(क) से (ग) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आई०जी०एफ०आर० आई०), झांसी द्वारा विकसित की गई

चारे की नई किस्मों का विवरण अनुपत्र में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग के चारा उत्पादन और प्रदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्यों के बीज निगमों जैसे विभिन्न संगठनों के जरिये विकसित की गई नयी किस्मों के बीजों को बढ़ाने (मल्टीप्लाई) करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(ग) भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ने नाभिक (न्युक्लियस) बीज और प्रजनक (ब्रीडर) बीज के उत्पादन के काम को संगठित करने का काम शुरू कर दिया है। कृषि और सहकारिता विभाग के चारा उत्पादन और प्रदर्शन से संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र मूल बीजों के उत्पादन का काम शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राज्यों के बीज निगमों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्यों के बीज निगमों द्वारा प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया जाएगा।

अनुपत्र

आई०जी०एफ०आर०आई०, झांसी में विकसित की गई चारे की किस्में

फसलें/किस्में घासें	आई०आर०* आर०** पी०***	उगाये जाने वाले क्षेत्र	हरे चारे की उपज टन/ हैक्ट०
1	2	3	4
बीनानाथी घास (पैनीसिटम पेडीसेलेटम)			
बुन्देल–1 (आई०जी०एफ०आर०आई०–43–1)	आर०	समस्त भारत	60–70
बुन्देल–2 (आई०जी०एफ०आर०आई०–4–2–1)	आर०	समस्त भारत	55–70
आई०जी०एफ०आर०आई०–3808	आई०आर०	आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र	50–60
अंजन घास (सेनक्रस सिलिआरिस)			
आई.जी.एफ.आर.आई.–3108	आई०आर०	उत्तर मध्य भारत के शुष्क क्षेत्र	15–20
आई.जी० एफ० आर० आई०–3813	पी०	—वही—	
मारवल घास (डिकैंथियम एनुलेटम)			
आई.जी.एफ.आर.आई.–एस–495–10	आई०आर०	उत्तर एव मध्य भारत के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र	20–25
हाथब्रिड नेपियर			
आई.जी.एफ.आर.आई.–सं0–7	आई०आर०	समस्त भारत (अम्लीय मिट्टी और उपोष्ण क्षेत्र)	130–150
आई.जी.एफ.आर.आई.–सं0–10	आई०आर०	—वही—	140–160

1	2	3	4
आई०जी०एफ०आर०आई०–सं०–3 (स्वेतिका–1)	आई०आर०	उ०प्र०, म०प्र०, उत्तरी आ०प्र० के पहाडी क्षेत्र, पंजाब	120–130
सं०–6	पी०	—वही—	120–130
जई			
जे०एच०ओ०–822	आई०आर०	मध्य भारत	45–55
जे०एच०ओ०–817	पी०	मध्य भारत	45–50
जे०एच०ओ०–810	पी०	शीतोष्ण क्षेत्र (कश्मीर)	55–60
फलीदार			
बरसीम			
वारडल (आई०जी०एफ०आर०आई०–99–1)	आर०	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, म० प्रदेश, विहार, प० बंगाल	90–115
रिजका			
चेतक (आई०जी०एफ०आर०आई०–244)	पी०	उत्तर भारत, हि०प्र०, म० प्रदेश	80–95
लोबिया			
कोहिनूर (आई०जी०एफ०आर०आई०–450)	आई० आर०	समस्त भारत (गर्मियों के लिये)	25–30
सेम (फील्ड बीन)			
आई०जी०एफ०आर०आई० जे०एल०पी०–3 पछेती किस्म	पी०	मध्य भारत	25–30
आई०जी०एफ०आर०आई० जे०एल०पी०–6 पछेती किस्म	पी०	—वहीं—	25–30
आई०जी०एफ०आर०आई० जे०एल०पी–4 पछेती किस्म	पी०	—वही—	23–26
ग्वार			
आई०जी०एफ०आर०आई० 212–1	पी०	उत्तर–मध्य एवं पश्चिमी भारत	25–30
आई०जी०एफ०आर०आई० 2395–2	पी०	—वही—	24–28
आई०जी०एफ०आर०आई० 1019–1	पी०	—वही—	24–28
आई०जी०एफ०आर०आई० 24–1	पी०	—वही—	24–28

*आई०आर०—जारी करने के लिए पहचान की गई**आर०—जारी की गई***पी०–आशाजनक

डा० गोविन्द दास रिछारिया : सभापति महोदय, जिस तरह से सूखा पड़ने के ऊपर माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बताया कि हम अन्न के मामले में स्वावलम्बी हैं। इसी तरह से चारा अनुसंधान केन्द्र ने भी इस तरह का आविष्कार किया है, इस तरह की घासें विकसित की हैं और भूमि पर सूखा पड़ने पर पशुओं को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है या इस तरह की योजना बनायी है कि इस योजना के अंतर्गत चारे के मामले में देश को और देश में रहने वाले पशुओं को स्वावलम्बी कह सकें और वह कह सकें कि किसी भी तरह का सूखा पड़ने पर आत्मनिर्भरता रहेगी ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : सभापति महोदय, यह सवाल सूखा पड़ने का नहीं था। सवाल तो यह है कि चारे के बारे में, फोडर के बारे में क्या अनुसंधान इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है? किस किस्म के बीज पैदा किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोडर पैदा किया जा सके। महोदय, पिछले कई सालों से अनुसंधान चल रहे हैं और 23 नए किस्म के बीज इसमें पैदा करने जा रहे हैं। तीन किस्म के रिलीज कर दिए हैं, आठ किस्म के बीज रिलीज होने के लिए रेडी हैं और 12 किस्म के बीज जल्दी रिलीज होने की आशा है। लेकिन जहां तक सूखे का ताल्लुक है, सूखा पड़ने की वजह से फोडर पैदा करने का सवाल है, वह अलग स्कीम है। उस पर भारत सरकार की तरफ से 9 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है ताकि किसानों की सहायता की जा सके और मुल्क में ज्यादा-से-ज्यादा फोडर पैदा किया जा सके।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : कब तक यह किया जा सकेगा ?

श्री भजन लाल : चालू है।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : सभापति महोदय, मैंने प्रश्न किया कि कितने किस्म की घासें विकसित हुई हैं तो आपने उत्तर दिया। उस प्रश्न का जो आखिरी भाग था वह यह था कि इस योजना के अंतर्गत आप उस में क्या-क्या करने जा रहे हैं। उसका आपने विस्तार से जवाब नहीं दिया। आखिर अनुसंधान केन्द्र केंद्रीय सरकार ने इसीलिए स्थापित किया है कि चारे के मामले में देश स्वावलम्बी रहे। इसीलिए वहां बड़े-बड़े वैज्ञानिक आए और वहां पर घासें विकसित की हैं। तो क्या आपने वहां पर प्रांतीय सरकारों से समन्वय स्थापित कर के सारे देश में उसके बीजों को पहुंचाया है ?

श्री भजन लाल : संस्थान अनुसंधान किसी भी सीड पर हो, उसका पूरा अनुसंधान करके, टेस्ट करके बाद में रिलीज किया जाता है और रिलीज होने के बाद फील्ड में जाकर लोगों को पूरी जानकारी दी जाती है कि इस बीज को इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से बोना है, इतनी खाद देनी है, इतना पानी देना है--सारी जानकारी उसके संबन्ध में दी जाती है। हमारा सवाल था झांसी केन्द्र के बारे में। उसके द्वारा हम 23 किस्म के बीज तैयार करने जा रहे हैं। तीन वेरायटीज को रिलीज कर दिया है। आठ तैयार हैं जो इस साल रिलीज हो जाएंगी और बाकी 12 के बारे में भी आशा है कि हम बहुत जल्दी उनको भी रिलीज कर देंगे।

श्री दयानन्द सहाय : सभापति महोदय, अपने देश में मनुष्य के लिए खाने के तेल की कमी है और हम हर साल हजारों टन तेल आयात करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी पापुलेशन जिसे कैटल वैल्थ कहते हैं, उनके भोजन में चिकनाई की कमी को दूर करने के लिए जरूरी था कि तेल का, चिकनाई का इंतजाम हो। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट स्तर पर वे नीति में एक परिवर्तन कराएंगे कि आगे से हम खाने का तेल न मंगाकर खाने के तेल के सीड मंगाएं ताकि मनुष्य की और अपने कैटल वैल्थ दोनों की जरूरत पूरी हो सके ?

श्री भजन लाल : महोदय, यह सवाल ओं के चारे के बारे में है। इसमें दूसरा सवाल नहीं आता है। लेकिन यह ठीक बात है कि इन्होंने जो कहा कि पशुओं के चारे में प्रोटीन होना चाहिए चिकनाई होनी चाहिए जिससे कि अच्छा दूध और अच्छा मक्खन दूध में से निकल सके। इसी बात को लेकर के अच्छी किस्म का घास पैदा किया जाता है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*84. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government are considering a plan for modernisation/expansion of the Salem Steel Plant; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) Government have sanctioned installation of Second Sendzimir Mill at Salem Steel Plant on 2nd March, 1988 at an estimated cost of about Rs. 70 crores. The project is scheduled to be completed in 42 months. After completion of the project, capacity of Salem Steel Plant for production of Stainless Steel would increase to 70,000 tonnes per annum.

Performance of NDDB's Vegetable Oil Project

*85. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NDDB's vegetable oil project financed by CLUSA-CIDA has more than three lakh farmers who have joined in 2500 cooperatives in seven States and increased oilseeds production considerably and if so, the details thereof;

(b) the per hectare production of oilseeds in the above States before and after the advent of NDDB-CLUSA-CIDA project; and

(c) whether it has not been possible to grow additional 2-3 quintals/ha. of oilseeds in order to stop all imports of vegetable oils as has been achieved in the case of milk by NDDB with EEC-World Bank CLUSA and CIDA support?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) The Project "Restructuring Edible Oil and Oilseeds Production and Marketing" under NDDB has covered about 4 lakh farmers under 3100 cooperative societies in seven States, i.e., Andhra Pradesh, Gujarat; Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Tamil Nadu.

Despite unfavourable weather conditions, the yield of groundnut crop in the Project districts in the States of Orissa and Karnataka and of rapeseed mustard in Gujarat showed improvement. The yield per hectare of soyabean in Madhya Pradesh also increased. However, the yield per hectare of groundnut in the Project districts of Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu was affected due to drought conditions.

(c) With a view to achieving self-reliance in oilseeds and vegetable oils, Government is making every effort to increase the production of oilseeds in the country, through national programmes, like the National Oilseeds Development Project and Oilseeds Production Thrust Project. A Technology Mission on Oilseeds has also been set up to coordinate the various activities relating to production and processing of oilseeds. As a result of these efforts, there has been increase in the production and yield per hectare of oilseeds.